hearty welcome to the leader and other members of the delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here they would be able to see and learn more about our parliamentary system, our country and our people, and their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and the Czech Republic. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of the Czech Republic.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS— Contd.

(Q. No. 202 - Contd.)

श्री सुरेश पचौरी: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रमुख रूप से चार सुपर इंटेलिजेंस और सीक्रेट एजेन्सीज हैं जिनके पे-स्केल अलग-अलग हैं और जो अलग-अलग कैटेगिरी की हैं। इनमें भी कुछ ऐसी एजेन्सीज हैं जिनकी सिफारिश उस पे-स्केल के लिए जो उन्हें वर्तमान में प्रदान किया जा रहा है, फिफथ पे-कमीशन ने रिकमेण्ड नहीं किया था। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि वे एजेन्सीज कौन-कौन सी हैं? कुछ ऐसी एजेन्सीज हैं जिनकी सिफारिश फिफथ पे-कमीशन ने की थी लेकिन अभी तक वे नोटिफाई नहीं हुई है। वे ऐजेन्सीज कौन-कौन सी है? तीसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं, वे कब से विचाराधीन हैं और कब तक विचाराधीन रहेंगे और उनपर कब निर्णय लिए जाएंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सर, 1997 में पांचवें पे-कमीशन ने अपनी सिफारिशें की थी और वे अलग-अलग पेजिज में की थी। उनको इम्पलिमेंट किया जा रहा है। जहां तक चार एजेन्सीज की बात है, उनके बारे में विस्तृत चर्चा 5 अगस्त, 1998 की बैठक में हुई थी जिसमें इस विभाग के लोग और वित्त मंत्रालय के लोग, सेक्रेटरी एक्सपेंडीचर सब लोग बैठे थे। उस समय जो निर्णय हुए वे जनवरी, 1999 में इम्पलिमेंट हो चुके हैं। कुछ उनमें से शेष रहे जिनमें से दो-एक का मैने उल्लेख किया। अगर सभी का उल्लेख करें तो मैं कहूंगा कि उनमें से प्रमुख है:

(1) Parity of pay-scales between R.A.S. and I.F.S.;

(2) Grant of pay-scales to medical officers of the S.S.B. on C.H.S. pattern; (3) Grant of cash compensation to all non-gazetted personnel for working on holidays; (4) Grant of regular pay-scales to Tibetan female nursing assistants on par with their counterparts in the Army.

ऐसे पांच - छः इश्यूज हैं जो पेंडिंग हैं, कन्सीड्रेशन विद दि गवर्नमेंट। अन्यथा बाकी जितने निर्णय थे उनकी विस्तृत रूप से चर्चा पांच अगस्त की बैठक में होकर जनवरी में इम्पलीमेंट हो गए।

श्री सुरेश पचौरी: सर, मैने इस बारे में जानना चाहा था कि वे कौन सी एजेन्सीज हैं जिनकी अनुशंसा पांचवें वेतन आयोग ने की है और जिन्हें बढ़ा हुआ पे स्केल दिया जा रहा है। उनके नाम दिए जाएं?

श्री सभापति: चलिए हो गया।

अमरीकी सीमाशुल्क अधिकारियों का भारत का दौरा

* 203. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य":** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सीमाशुल्क अधिकारियों का एक दल भारत के वस्त्र उद्योग में काम कर रहे बाल श्रमिकों की स्थिति की जांच करने के लिये भारत आ रहा है;

(ख) क्या विदेश मंत्रालय ने इस दौरे की मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त दौरे का औचित्य क्या है ; और

(घ) इस दौरे का भारत का सम्प्रभुता पर क्या असर पड़ने की संभावना है?

(श्री काशी राम राणा) वस्त्र मंत्री: (क) से (घ) जी हां, भारत सरकार के अनुमोदन पर 3 अमरीकी सीमाशुल्क अधिकारियों के एक दल ने फरवरी, 1999 में भारत का दौरा किया। उनके दौरे का उद्देश्य भारत में हाथ से बुने कालीन उद्योग में बलकृत/करारबद्ध बालश्रम पर जानकारी प्राप्त करना था। उनके आने से भारत की प्रभुत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य": सभापति जी, एक के बाद एक सरकारों ने यह फैसला किया कि हमारे बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा जाए ताकि वे बालश्रमिकों के रूप में काम न कर सकें। लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार की आबादी और गरीबी की परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए हमारे यहां बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है। यह बात अपने स्थान पर सही है न चाहते हुए भी। इसके लिए हमारी राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार समय-समय पर निर्देश जारी करती रही हैं और कानून भी

बनाती रही हैं। जहां तक अपनी सरकारों का प्रश्न है वे रियल्टीज के आधार पर, उसको देखकर काम करती रही हैं। इस समय जो मेरा प्रश्न उठा है उसका कारण यह है कि अमरीका के कस्टम डिपार्टमेंट में लोगों को, सीमा शुल्क के लोगों को यह अनुमति दी गई है कि वे इस बात का निरीक्षण करें कि हमारे कालीन उद्योगों में व अन्य स्थानों पर जाकर देखें कि बालश्रमिकों से काम लिया जा रहा है या नहीं। उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि प्रभुसत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है जिसके अन्तर्गत एक देश दूसरे देश में जाकर वहां के उद्योगों में काम करने वालों के बारे में छानबीन करे। अगर ऐसा समझौता हुआ है तो वे कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या कारण हैं कि अमरीका के सीमा शुल्क विभाग के लोगों को यहां छानबीन की अनुमति दी गई?

श्री काशी राम राणा: सर, हमारे यहां जो कालीन उद्योगों में बाल श्रमिक काम करते हैं उनकी छानबीन के लिए अमेरिकन कस्टम ड्यूटी के लोग आए हैं, इस बारे में माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है। सर, ऐसा कोई समझौता किसी देश से नहीं है। फिर भी हमारी कंडीशन और हमारी शर्तों के आधार पर जो हमारी फोरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने उसे परमिशन दी। सर, हमारा कालीन यू०एस०ए० में ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। इतना ही नहीं बाल श्रमिक के बारे में यू०एस० कांग्रेस में बार-बार कई बिल लाए जा रहे हैं, जर्मनी में भी ऐसी कोशिश हो रही है। सर, हमारा जो कालीन एक्सपोर्ट होता है जर्मनी और अमरीका में, इसमें बहुत बड़ा इम्पेक्ट, बहुत बड़ा ऑब्सटेकल अवरोध उसमें से पैदा होता है। हमें कई बार, हमारी जो एम्बेसी हैं, चाहे वह अमरीका में हो, चाहे जर्मनी में हो वे कोरिफिक्रेशन देते रहते हैं कि हमारे यहां जो बाल श्रमिक है वे बाल श्रमिक जैसे अमरीका के जो लॉज हैं वे जो इंटर प्रेटेशन करते हैं, जो इंटेचर और फोर्स का लेबर का करते हैं वैसा बाल श्रमिक भारत में नहीं है। भारत का जो कानून है, जो लेबर लाज है, बाऊंड चाइल्ड लेबर के बारे में है, उनके मुताबिक यहां पर ऐसा इंटेचर और फोर्स या चाइल्ड लेबर यहां पर नहीं है। यह भी हमने कई बार एक्सप्लेनेशन किया है लेकिन फिर भी यह जो तीन कस्टम ऑफीसर की टीम यहां आई थी हमने अपनी कंडीशन उसके सामने रखी कि वह केवल इन्फोर्मेशन कलेक्ट करेगी, इनवेसिटगेशन नहीं करेगी। वही काम उन्होंने किया और हमारे जो ऑफिसल हैं, चाहे टैक्सटाइल, लेबर, कस्टम, एक्साइज के हो उन्होंने इस टीम के सामने ब्रीफ किया था।

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य": सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह इन्फोर्मेशन कलेक्ट करेंगे इनवेस्टिगेशन नहीं करेंगे। इन दोनों में भेद क्या है? यह माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि बिना इन्फोर्मेशन कलेक्ट किए कोई इनवेस्टिगेशन कैसे करेंगे और इनवेस्टिगेशन किस लिए करेंगे? जो माननीय मंत्री जी ने वर्णन किया है कि अमरीकी संसद में और जर्मनी में भी ऐसे सवाल उठे हैं जिसकी वजह से हमारे कालीन उद्योग पर प्रभाव पड़ने वाला है और इस कारण से उन्होंने अनुमति दी, और वे हमारी शर्तों पर आए हैं। एक तो मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि हमारी शर्तें क्या थीं और ऐसी आवश्यकताएं क्यों पड़ीं? दूसरा उन्होंने कहा कि फरवरी में वे निरीक्षण कर चुके हैं, जो निरीक्षण करने के बाद उसका परिणाम क्या निकला? और क्या भारत सरकार भी इस बात का प्रयत्न करेगी कि अमेरीका में बनी हुई सामग्री जो हमारे देश में आती है और जो हमारे यहां हानिकारक है, चाहे दवा के रूप में, बाकी है, वहां पर भी निरीक्षण करने के लिए क्या हम इसी प्रकार अपनी टीम भेजेंगे?

श्री काशी राम राणा: सर, अमरीका में जो कानून है चाइल्ड लेबर के बारे में, वह चौदह साल से बिली दि एज ऑफ फेरटीन उससे कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो वह अलउ नहीं करना ऐसा यू०एस०ए० कस्टम को वहां पर आदेश है और इसीलिए चाइल्ड लेबर के बारे में यहां पर वे आए। सर, दूसरी कि हमने शर्त रखी थी कि सर, अगर एम्बेसी वाशिंगटन Our Embassy in Washington said, "After consulting the MEA and on the advice of the Ministry of Commerce, with the approval of the Commerce Minister, granted visa to the U.S. Custom officials about their visit to India under the following conditions: First condition is the visit must only be for the purpose of information gathering and not for conducting enquiries on forced child labour in India." सर, मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि तीन ऑफीसर की टीम आई थी उसमें एक ही ऑफीसर वहां गया था, दो ऑफीसर्स ने हमारी जो अलग-अलग मिनिस्ट्री हैं, उसके सामने ब्रीफकिया था। सर, और भी कंडीशन्स हैं यदि आप परमिट करें तो मैं पढ़ लूं। माननीय सांसद ने पूछा है कि इसका क्या परिणाम आया, तो सर, जो आफिसर टीम गई थी, उन्होंने हमारे जो चाइल्ड लेबर के बारे में स्कूल चलते हैं, वे देखे, जो लूम थी वे भी देखी। हमारे आफिसर ने जब इनके बारें में उन्हें पूछा तो उन्होंने सैटिस्फैक्शन प्रकट किया है।

श्री रूमन्दला रामचन्द्रैया: सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा यह प्रश्न है कि बुनकर बाल-कार्मिक कितने हैं और उनकी अच्छाई के लिए पाठशाला सुविधा और कुछ अच्छी प्रणाली बनाने के लिए क्या विचार हो रहा है?

MR. CHAIRMAN: That does not arise out of this question. Mr. Khuntia. *(Interruptions).* Mr. Khuntia.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has said that the American officers were very much satisfied. But do we require the certificate of any country about the child labour or anything else? We are allowing them to see our child labour. Has the hon. Minister got any information about the child labour engaged in America or Germany or any European country? Will the Government also try in future to get information about the child labour engaged in all the work in the European countries?

SHRI KASHIRAM RANA: It is not necessary to get a certificate from the American customs. It is not necessary.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Mr. Chairman, Sir, I am coming to the question directly. Has the Government of India taken note of the warning issued by the incoming Director-General of the ILO, Mr. Somaria, that the growth of child labour will be further increased due to the resistance in the economic growth in Asia? If so, what actions are taken or proposed to be taken to arrest the growth of child labour in our country due to the slow-down in the economic growth? It is a direct question.

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, the question concerns the Labour Minister.

MR. CHAIRMAN: It is not a relevant question.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: It is related to child labour.

MR. CAIRMAN: No, it is not a relevant question.

MISS SAROJ KHAPARDE: Sir, may I know from the hon. Textiles Minister the number of child labour involved in the Indian textile industry and since when the child labour have been involved in this field? What initiatives has the Ministry of Textiles taken to stop the engagement of child labour in the textile sector? I would also like to know from the hon. Minister this. What have been the reasons for other countries showing interest in the matter of engagement of child labour in India's textile industry or the industrial sector? Has the Ministry of Textiles considered these aspects or not?

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, so far as child labour in India is concerned, the number of child labour is declining year by year.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Please give us the numbers. My colleague was putting the same question.

MISS SAROJ KHAPARDE: Sir, my question is since when the child labour has been involved in the textiles sector and what is the number?

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, the question was raised about textiles, particularly, 'Kaleen' or carpet. In this connection, according to the judgment of the Supreme Court delivered on 10th December, 1996 ....*(Interruptions).* The Supreme Court has given some directions and according to them,... *(Interruptions)....* the Government is taking steps.

MISS SAROJ KHAPARDE: Sir, I have put a specific question to the hon. Minister. Since when has child labour been involved in the textile industry and how many of them are there?

SHRI KASHIRAM RANA: Everybody knows that there is child labour not only in this carpet industry but in other industries also. *(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: She is asking only about this industry.

SHRI KASHIRAM RANA: So, I am giving my answer.

MISS SAROJ KHAPARDE: Sir, the Minister has not replied to my question.

MR. CHAIRMAN: Yes, he has not replied to your question.

MISS SAROJ KHAPARDE: This is not fair. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: If he is not replying,

what can I do? *(Interruptions)*

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, you sould give a direction to the Minister to do so. *(Interruptions)*

MISS SAROJ KHAPARDE: Sir, the Minister has not done his home work. This is not fair. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Shri Ashok Mitra. *(Interruptions)*

MISS SAROJ KAPARDE: Sir, the Minister has not replied to my question.

I wanted to know what the Ministry of Textiles is doing about the problem of child labour. *(Interruptions)*

इतना इम्पारटेंट क्वेश्चन हैं इसका मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। आप मंत्री जी को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारे सवाल का जवाब कहां से आएगा। ...(व्यवधान)

SHRI ASHOK MITRA: Sir, this is a very serious issue. Now, some of us have been wondering as to how does the American State Department get the audacity to announce that we are going to sign the CTBT in June even wen the Prime Minister and the External Affairs Minister keep saying, no? They assume that they can dictate to us what our policy sould be. *(Interruptions)* As far as the labour issue is concerned, this is something which has been discussed at length at the international fora and it has been decided that even the World Trade Organisation does not have any jurisdiction in deciding on the labour standardards. This is a matter which belongs exclusively to the International Labour Organisation, and it is for them to investigate if there is any complaint about whether in some country, child legislations have been in force, and where in force, they have been violated. No individual country has the right to take upon itself the prerogtive of deciding whether some other country is conforming to correct labout standards or not. I would like to know from the Minister of Textiles whether he took the care to inquire of the I..L.O or the W.T.O. whether the Government of the United States has lodged any complaints with them or not. If they have not done so, our own, we have no business to request the United States and say; "Sir, you are our God. You must come and decide whether we are conforming to the labour standards or not. "I am sorry to say so. But Mr. Minister, that you have done, puts us all into shame. *(Interrruptions)*

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, the Government will keep in mind the suggestion of the hon. Member. *(Interruptions)* Sir, under any circumstance, the Government will never go in for....*(Interruptions)* Moreover, the U.S. Government is likely to raise this issue in the next inter-ministerial meeting of the WTO because our hon. friend has raised some issues regarding the WTO.

KUMARI NIRMALA DESHPANDE: Sir, as a social worker involved in the field of elimination of child labour, we feel that perhaps there is a design to block Indian exports. So, will the Minister kindly look into this questions? हिन्दी में एक कहावत है, 'बुढ़िया के मरने का गम नहीं, पर मौत ने घर देख लिया'। कहीं ऐसा न हो इस बहाने मौत हमारा घर देख ले।

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, I despite so many obstacles, despite so many difficulties, our export of carpet is going up and up. .....*(interruptions)*....

कुमारी सरोज खापर्डे: मंत्री जी, इसी चीज़ को गर्व से बोलिए। .....(व्यवधान)

SHRI KASHIRAM RANA: I am giving the details. Sir, our export is going up....*(interruptions)*....Sir, in 1995-96 our export was Rs. 1,959.80 crores, but nowadays....*(interruptions)*....

SHRI S. S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, this is not the question raised by her.

MR. CHAIRMAN: You please sit down.

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, in the years 1996-97, 1997-98.....*(Interruptions)*.....

MR. CHAIRMAN: She asked something else.

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, I am giving the answer.....*(interruptions)*.....

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, it is really intriguing that the custom officials of the U.S. Government are coming to inspect our factories to collect information in connection with our exports. One can understand that when it is a questions of relationship between a buyer and a seller, the buyer, in order to satisfy

himself, sends some representatives to look into the service conditions. On the involvement of child labout, there is an agitational movement going on it some of these countries and there is a strong public opinon in favour of that. I am not going into that aspect. But this is for the first time that an official team is coming. After all, the relationship between an exporter and an importer is different from the relationship between a buyer and a seller. Here, it is a question of relationship between the buyer and the seller. So, if they send their team to satisfy themselves as to whether the products which they are buying for their customers is up to the standard or not, that is one thing. But what is the rationale behind allowing the revenue officers and the customs officers of the United States to come and satisfy themselves? They may have a compulsion under their own domestic laws, but surely, we are not going to comply with their request to help them to overcóme the problems of their domestic growth. There is no international obligation..

So far as the international obligation is concerned, we have to fulfill that, and we have given our schedule about removal of child labour, what steps we are going to take to remove that. That is our commitment which we have given to the W.T.O. We have never agreed, India, till today, has never agreed to it that W.T.O. should have the right to determine the internaitonal labour standards. Therefore, the Minister should clear it out. Sir, as there is no time left, I think, if you agree, it would be a fit case to have a Half-an-Hour Discussion in which we can express our views and the Minister can come prepared.

MR. CHAIRMAN: You give notice. We will see to it. Mr. Duraisamy.

SHRI KASHIRAM RANA: May I reply, Sir?

MR. CHAIRMAN: He wants to have a discussion....(*interruptions*)...

MISS. SAROJ KHAPARDE: He can reply to it, Sir....(*interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: Do you want to say something?....(*interruptions*)... Mr. Duraisamy.

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir, I am not at all satisfied with the answer given by the Minister. We are having suitable and sufficient rules and regulations to prevent child labour, not only in factories, not only in industries, but also in domestic areas. The respective State Governments are also penalising those who are engaging child labour in our homes. Under these circumstances, it is not necessary for the Government to allow the foreigners to come and study the conditions of child labour. After knowing the sentiments of the House, will the Minister stop the foreign team from studying the conditions and save the sovereignty of India?

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, the customs officers of the U.S. Government came here only to get the information.

I have already explained that ...(*interruptions*)....

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, the customs officials can get the information from the Embassy.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Setting up Power Trading Corporation

*204. SHRI RAGHAVJI:
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision on setting up of Power Trading Corporation, as a joint venture of NTPC, NHPC, PGIC and PFC to undertake mega power projects;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) whether any task force is proposed to be constituted to watch the setting up and Commissioning of these mega projects within a time frame?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARMANGALAM): (a) and (b) Yes, Sir,